www.tamsasanket.com
वर्षः 05 || अंक 283 || लखनऊ
शुक्रवार
16 जनवरी 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
75 आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा

दैनिक तमसा संकेत

>> डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र
https://epaper.tamsasanket.com
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

मौसम
सूर्योदयः 06:57
सूर्यास्तः 05:36
अधिकतमः 18°00
न्यूनतमः 08°00

>> पेज 03

विशेष समाचार | क्या ईरान में इस्लामी शासन एक ... >> पेज 02 | झूठा एससी-एसटी केस दर्ज कराने ... >> पेज 04 | अल्लू अर्जुन-लोकेश कनगराज की ...

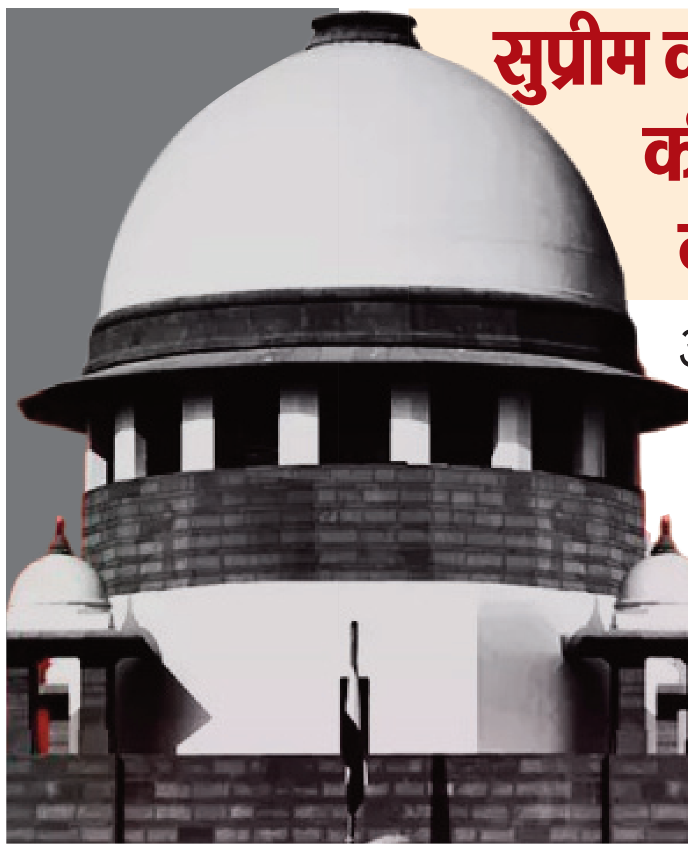

सुप्रीम कोर्ट में ईडी की 3 बड़ी दलीलें...

- रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचीं और इलेक्ट्रोनिक डिवाइस और दस्तावेज अपने साथ ले गईं। ममता के साथ बंगाल डीजीपी भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे। पुलिस ने ईडी अफसरों के मोबाइल छीन लिए। सीएम मीडिया के सामने भी गईं। इस तरह ईडी का मनोबल गिरता है। उनके काम में बाधा आती है।
- हम 14 जनवरी को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई से संतुष्ट नहीं है। हमें काफी परेशानी हुई। सुनवाई के दौरान बार-बार माइक बंद हो रहा था। कोर्ट में भीड़ इकट्ठा करने के लिए को बस और गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस को आदेश देना पड़ा कि वकीलों के अलावा किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी।
- ईडी आर्टिकल 21 के तहत अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आई है। ईडी अधिकारियों को धमकियां दी गई थीं। हम हाईकोर्ट नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं सीबीआई मामले की जांच करें। मामला सीबीआई के पास गया तो मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है।

आई-पीएसी रेड मामले में ममता सरकार को नोटिस, कहा- एजेंसी के काम में रुकावट न डालें

सुप्रीम कोर्ट की ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक

भाजपा ने कहा- आज ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इससे साबित हो गया है कि जंगल राज कैसा होता है। राज्य सरकार को जांच एजेंसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी ने फाइलें ही ले लीं। जो सोचता है कि वह संविधान से ऊपर हैं। अब यह नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दायर एफआईआर पर रोक लगा दी है।

2,742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा आई-पीएसी छापा मामला

ED ने कोयला तस्करी से जुड़े 2,742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर I-PAC डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। CBI ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को FIR दर्ज की थी। ED ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की थी। यह मामला अब 5वें साल में है, लेकिन कार्रवाई ठीक उस वक्त सामने आई, जब बंगाल में मार्च-अप्रैल 2026 में चुनाव होने हैं। I-PAC भारत की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है, जो राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। आरोप है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए I-PAC तक ट्रांसफर हुए। जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने जांच में बाधा डाली और सबूत नष्ट किए।

"सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है? ईडी ने 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म (आई-पीएसी) डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस दौरान सीएम ममता वहां बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंचीं और अपने साथ सबूत लेकर चली गईं। इस पर जांच एजेंसी ने कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है।"

नोटिस

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। I-PAC रेड मामले में ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और दो हफ्तों में जवाब मांगा। कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ED के काम में दखल न डालें। एजेंसी को अपना काम करने दें। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर भी रोक लगा दी है। कलकत्ता हाइकोर्ट ने I-PAC रेड मामले में बुधवार को TMC की याचिका खारिज कर दी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ने 8 जनवरी को प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। इस पर जांच एजेंसी ने कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। I-PAC डायरेक्टर प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी थी। ED वह जब्त करना चाहती थी। ममता सिर्फ उनका और आईफोन लेकर गई थीं। CM ने रेड में कोई दखल नहीं डाली थी। आपका दावा गलत है। अगर ED का इरादा कुछ जब्त करने का होता, तो वे जब्त कर लेते, लेकिन कुछ भी जब्त नहीं किया गया।

9 जनवरीः ममता बनर्जी ने कोलकाता में मार्च निकाला

9 जनवरी को TMC के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर दो FIR भी दर्ज कराई है। उन्होंने कोलकाता में मार्च भी निकाला। इस दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव हैं। उन्होंने कहा- दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके सबूत हैं। जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। ममता वहां कुछ देर रुकीं। जब बाहर निकलीं, तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद वे I-PAC के ऑफिस भी गईं। उन्होंने कहा- गृहमंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं।

सीएम ने कहा था- कोयला घोटाले का पैसा शाह को भेजा गया

ममता ने 9 जनवरी को मार्च के दौरान आरोप लगाया है कि कोयला घोटाले का पैसा सुवेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है इस पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने बनर्जी को मानहानि का नोटिस भेजा। नोटिस में उन्होंने 72 घंटे के भीतर कथित आरोपों से जुड़े सभी सबूत पेश करने की मांग की गई।

ब्राह्मणों को चोखा-बाटी नहीं, सम्मान चाहिए : मायावती

बर्थडे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट सर्किट, धुआं भरा

तमसा संकेत, एजेंसी

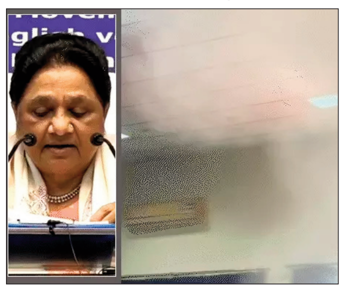

लखनऊ। बसपा प्रमुख मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफरा-तफरी के हालत बन गए। दरअसल, लखनऊ के पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते वक्त हॉल की छत पर लगी लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया। चिनगारी निकलने लगी। देखते ही देखते हॉल में धुआं भर गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। तुरंत ही सुरक्षाकर्मी हरकत में आए और अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल कर हालात पर काबू पाया। तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। मायावती बिना केक काटे और मीडिया के सवाल लिए बिना ही रवाना हो गईं। इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बड़ा बयान दिया। कहा- ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए। हमारी सरकार बनने पर ब्राह्मणों की चाहत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी या सपा के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने बसपा की चुनावी रणनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा- बसपा पूरे देश में हर चुनाव अकेले ही लड़ेगी। यूपी में होने वाले चुनाव में बसपा अकेले ही उतरेगी।

भारत से संघर्ष के बाद हमारे फाइटर-जेट्स डिमांड में : शहबाज शरीफ

6 मुस्लिम देशों को जेएफ-17 बेचने की बात चल रही

दावा

तमसा संकेत, एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का दावा है कि भारत के साथ पिछले साल मई में हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की डिमांड बढ़ गई है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक, उन्होंने बुधवार को कहा किया कि कई देश पाकिस्तानी फाइटर जेट्स खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किन फाइटर जेट्स की डिमांड बढ़ी है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कई देश पाकिस्तान JF-17 थंडर फाइटर जेट्स खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इनमें बांग्लादेश, सूडान, लीबिया, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने 12 जनवरी को पाकिस्तान के वायु सेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की और करीब 40 JF-17 खरीदने पर बात की। वहीं बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार के मुताबिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी JF-17 फाइटर जेट बेचेगा।

>> (शेष पेज 04 पर)

फास्ट न्यूज

शहीद जवान की मां मेडल लेते बेहोश हुईं

जयपुर। जयपुर के SMS स्टेडियम में आर्मी-डे पर गुरुवार शाम शौर्य संध्या कार्यक्रम में सेना के पैराट्रूपर्स उतरे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में पूरा स्टेडियम जय हो के नारे से गूंज उठा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया- ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आतंक की सोच खत्म नहीं होती है।

जम्मू-कश्मीर को दो अलग राज्य बनाने की मांग

श्रीनगर। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने जम्मू और कश्मीर को दो अलग राज्यों में बांटने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब दोनों क्षेत्रों के बीच सौहार्दपूर्ण अलगाव पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। लोन ने कहा कि कश्मीर ऐसे क्षेत्रीय रवैये को बर्दाशत नहीं कर सकता, जो लगातार कश्मीरियों को बदनाम करता रहा। देश के बाकी हिस्सों में यह धारणा फैलाए कि जम्मू देश के साथ है और कश्मीर आतंकवाद का क्षेत्र है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री सज्जाद लोन ने यह बातें बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं। कुछ दिन पहले भाजपा के जम्मू नॉर्थ से विधायक श्याम लाल शर्मा ने जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग की थी।

रांची ईडी ऑफिस में जांच करने पहुंची झारखंड पुलिस

रांची। रांची के ED ऑफिस में झारखंड पुलिस जांच करने के लिए पहुंची है। दरअसल, ED के दो अफसरों पर एक व्यक्ति ने पूछताछ के नाम पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ED दफ्तर में सदर DSP और एयरपोर्ट थाना के प्रभारी मौजूद हैं। वहीं ED ने सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को बुलाया है।

मंदिर में तोड़फोड़, पथराव में दो पुलिसकर्मी घायल

बीजेपी बोली- हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा

घटना

तमसा संकेत, एजेंसी

हैदराबाद। हैदराबाद के पुरानापुल इलाके में बुधवार रात मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। मुर्ती को नुकसान पहुंचाया गया। एक बैनर फाड़ने की कोशिश की गई। जिसके बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन हुआ प्रदर्शन दौरान पथराव, वाहन जलाने और पास की एक दरगाह को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुईं। पुलिस ने दो अलग-अलग केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात करीब 11:30 बजे मंदिर में मूर्तियों के क्षतिग्रस्त होने और बैनर फाड़ने की कोशिश की सूचना मिली। इसके बाद स्थानीय लोग मंदिर के पास जुटने लगे। नारेबाजी के

साथ विरोध शुरू हुआ और कुछ ही देर में भीड़ बढ़ गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने पथराव किया। इसमें दो पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। इसी दौरान एक दोपहिया वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक, भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पास स्थित एक दरगाह को भी नुकसान पहुंचाया।

>> (शेष पेज 04 पर)

130 से 150 सीटें मिलने का अनुमानः उद्धव की शिवसेना को 60 सीटें मिल सकती हैं

बीएमसी चुनाव : तीन एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को बहुमत

मतदान

तमसा संकेत, एजेंसी

मुंबई। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में गुरुवार को वोटिंग खत्म हो गई है। मतदान के बाद आए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के 3 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान है। भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 130 से 150 सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए 114 की जरूरत है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 60 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें आ सकती हैं। नतीजे शुक्रवार को आएंगे।

स्टेट इलेक्शमन कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने कहा कि सभी नगर निगम में शाम 5:30 वोटिंग खत्म हुई। करीब 50% मतदान का अनुमान है हालांकि अंतिम आंकड़े बाद में जारी होंगे। उधर शिवसेना यूबीटी ने मनसे के साथ अलांयस किया है।

>> (शेष पेज 04 पर)

आदित्य ठाकरे बोले- चुनाव में सिस्टम बहुत खराब

आदित्य ठाकरे ने कहा, आप देख सकते हैं कि मुंबई, पुणे और हर जगह चुनाव आयोग और नगर निगम का सिस्टम बहुत खराब हालत में है। पर्ची किसी दूसरे बूथ की, नाम अलग बूथ में है। कुछ जगहों पर नाम पुरुष का है जबकि फोटो महिला की है। सोचिए चुनाव अधिकारी कितनी गड़बड़ करते हैं। इन्हें हमारे पैसे से सैलरी दी जाती है, टैक्स देने वालों के पैसे से दी जाती है। इन पर सवाल उठाना जरूरी है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पक्की स्याही का यह मार्कर 2011 से इस्तेमाल में है।

चार साल देरी हो रहे चुनाव, 2022 से टल रहा

नगर निगम चुनाव हर पांच साल में होते हैं। बीएमसी का पिछला चुनाव 2017 में हुआ था। ऐसे में अगला चुनाव 2022 में होना था। उस दौरान निर्वाचन प्रक्रिया और वार्ड सीमाओं में बदलाव चल रहे थे। नए वार्ड नक्शे और सीटों का पुनर्विन्यास किया जा रहा था। बीएमसी में वार्डों की संख्या बढ़ाकर 227 से 236 करने का प्रस्ताव था। इस बदलाव के चलते पुरानी सीटों पर चुनाव करना संभव नहीं थ।

बीएमसी में सीटों का बंटवारा, बीजेपी-शिंदे साथ, कांग्रेस अलग लड़ रही

बीएमसी चुनाव में कुल 227 सीटों पर चुनाव हुए। भाजपा- शिवसेना (शिंदे गुट) में गठबंधन हैं। बीजेपी 137 सीटों पर लड़ रही है वहीं शिंदे की शिवसेना ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं।

शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, कई जगहें हैं जहां से शिकायतें आ रही हैं। कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि लगाई गई स्याही को अब साफ किया जा सकता है। पुरानी ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं। इन लोगों में सत्ता पाने का इतना लालच है। मैंने ऐसी बेशर्म सरकार कभी नहीं देखी। इसीलिए वे वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, ताकि वे पूरे देश में एक ही समय में धोखाधड़ी और गड़बड़ी कर सकें, और पूरे देश पर कब्जा कर सकें।

हादसा : इंजन को नुकसान, पार्किंग के लिए ले जाते समय कोहरे के कारण हादसा, यात्री-क्रू सुरक्षित

एअर इंडिया का विमान बैगेज कंटेनर से टकराया

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह 5:25 बजे एअर इंडिया का विमान बैगेज कंटेनर से टकरा गया। एयरलाइन ने बताया कि घने कोहरे में एयरबस A 350 विमान को पार्किंग के लिए ले जाया जा रहा था, तभी यह घटना हुई। हादसे में विमान के इंजन को नुकसान पहुंचा है। विमान में सवार सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। एयरबस A 350 की फ्लाइट AI101 दिल्ली से न्यूयॉर्क के बीच चलती है। ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण फ्लाइट को अपना मार्ग बदलना पड़ा और वह वापस दिल्ली लौट आई थी। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की। बताया कि दाहिने इंजन को नुकसान पहुंचा। दिल्ली से मुंबई जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट को 40 मिनट में ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। घटना 21 दिसंबर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोइंग 777-300ER AI887 फ्लाइट का दाहिना इंजन टेक-ऑफ के बाद बंद हो गया। उसमें ऑइल प्रेशर जीरो हो गया था। इसके चलते उसे दिल्ली एयरपोर्ट लौटना पड़ा।

विमान के नंबर-2 इंजन को नुकसान पहुंचा।

सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स सुरक्षित

एयरलाइन के अनुसार, घटना के बाद विमान को सुरक्षित रूप से निर्धारित पार्किंग स्थान पर खड़ा कर दिया गया। सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। विमान को जांच और जरूरी मरम्मत के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। एयरलाइन ने चेतावनी दी है कि इससे कुछ A350 रूट्स पर उड़ानों में बाधा आ सकती है। साथ ही, प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था और रिफंड पर काम किया जा रहा है। एअर इंडिया ने कहा, हम पैसेंजर्स को उनकी पसंद के अनुसार वैकल्पिक यात्रा या रिफंड दिलाने में मदद कर रहे हैं। एअर इंडिया की सर्वोच्च प्राथमिकता सिक्योरिटी है।

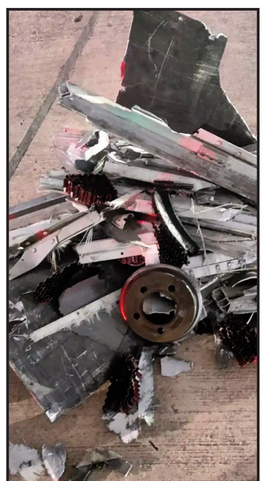

टक्कर से विमान का हिस्सा टूटकर गिर गया।

मकर संक्रांति : प्रयागराज में 91 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया

पीएम ने अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया, पतंगबाजी से दो दिनों में 17 लोगों की मौत

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली/भोपाल/लखनऊ। देशभर के कई हिस्सों में गुरुवार को भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। संक्रांति को लेकर गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी प्रमुख नदियों के तटों पर लाखों लोग सुबह से डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज माघ मेले में आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व है। संगम में शाम बजे तक 91 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज करीब डेढ़ करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान लगातार हादसे भी सामने आ रहे हैं। बीते दो दिनों में गुजरात में में 9 और राजस्थान में 6, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 1-1 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के वाराणसी के गंगा घाट

और पश्चिम बंगाल के गंगासागर में स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। पंजाब के अमृतसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सचखंड श्री दरबार साहिब में पवित्र स्नान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल का तिल के तेल से अभिषेक हुआ। भस्म आरती में भी तिल चढ़ाया गया और तिल के लड्डुओं का भोग लगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यानाथ ने मकर संक्रांति पर गुरुवार तड़के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी ने सुबह 3:40 बजे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। नाथ परंपरा के अनुसार, उन्होंने गुरु गोरखनाथ की पूजा-अर्चना की। इसके बाद गले में लटकी सीटी बजाई और दंडवत होकर प्रणाम किया। जल्लीकट्टू एक ऐसा खेल है, जिसमें भीड़ के बीच सांड छोड़ दिया जाते हैं। इस खेल में हिस्सा लेने वाले लोग सांड का कूबड़ पकड़कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कई सांड का कूबड़ ज्यादा से ज्यादा देर तक पकड़े रखने वाला ही विजेता होता है।

सम्पादकीय

बंगाल में बढ़ता घमासान

पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लगातार ऐसे प्रकरण घटित हो रहे हैं जिनकी वजह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। लगातार ऐसे प्रकरण घटित हो रहे हैं जिनकी वजह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सक्रिय होना बता रहा है कि भाजपा यहां चुनाव जीतने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपना रही है। चुनाव आयोग और ईडी दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं और दोनों की साख तभी कायम रहेगी, जब बिना राजनैतिक दबाव के ये कार्य करती दिखाई दें। लेकिन प. बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले हफ्ते ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली एजेंसी आईपैक के दफ्तर और उसके सहसंस्थापक प्रतीक जैन के घर ईडी ने अचानक दबिश दी। यह छापेमारी कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में दी गई थी और इसका कोई राजनैतिक मकसद नहीं था, ऐसा तर्क ईडी की तरफ से आया। जबकि टीएमसी का सीधा आरोप है कि यह राजनैतिक बदले की कार्रवाई थी और ईडी के जरिए अमित शाह टीएमसी की रणनीति चुराना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इस छापेमारी का विरोध किया, इसके खिलाफ रैली निकाली इसकी उम्मीद भाजपा को नहीं रही होगी। ईडी ने पहले कलकत्ता हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी के खिलाफ याचिका दी है कि उसने काम में बाधा डाली और ममता बनर्जी मौके पर आकर एक फाइल लेकर चली गईं। इधर टीएमसी ने भी हाईकोर्ट में याचिका दी थी। पिछले हफ्ते इस पर सुनवाई शुरु हुई, लेकिन भीड़ और हंगामे के कारण चल नहीं पाई। फिर बुधवार को फिर से सुनवाई हुई तो इसमें ईडी और भाजपा को बड़ा झटका लगा है। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू बार-बार यही अपील करते रहे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल है, इसलिए उस पर फैसला आने के बाद ही सुनवाई हो। राजू ने इस बात पर भी आपत्ति जाहिर की कि आई पैक की तरफ से अदालत में कोई मौजूद नहीं था। ईडी ने टीएमसी के आरोप खारिज करते हुए यह भी कहा कि उसने कोई दस्तावेज जब्त नहीं किए। सब कुछ ममता बनर्जी और उनके सहयोगी लेकर चले गए। इस पर टीएमसी की तरफ से पेश वकील मेनका गुरुस्वामी ने साफ कहा कि ईडी के इस बयान को दर्ज कर लिया जाए कि छापेमारी के दौरान कुछ भी जब्त नहीं किया गया। यानी भविष्य में अब ईडी किसी दस्तावेज को छापेमारी में बरामद सबूत के तौर पर पेश करना चाहे तो भी यह संभव नहीं होगा। क्योंकि ईडी ने खुद माना है कि उसने कुछ बरामद नहीं किया है। अदालत में टीएमसी ने आरोप लगाया कि ईडी राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर झूठे इल्जाम गढ़ रही है। फिलहाल ईडी की बार-बार अपील के बाद और टीएमसी की तरफ से दी गई दलीलों के बाद याचिका खारिज कर दी गई हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या फैसला आता है, ये देखना होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर ईडी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर आ सकती है। यानी जिस उम्मीद से ईडी की छापेमारी आईपैक पर करवाई गई थी और उसके बाद अदालत में भी टीएमसी को घेरने की कोशिश हुई थी, उसमें फिलहाल भाजपा को नाकामी हासिल हुई है। ममता बनर्जी अपने विरोधी को घेरने के लिए सड़क पर उतरना और लोगों को अपने साथ करने की राजनीति खूब जानती हैं। ईडी की छापेमारी प्रकरण ने ममता बनर्जी का ये कौशल भाजपा को याद दिला दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से अगर टीएमसी के खिलाफ फैसला आएगा, तो भी ममता बनर्जी उसे सहानुभूति के लिए इस्तेमाल कर लेंगी और अगर पक्ष में फैसला आता है, तब तो भाजपा की बड़ी हार तय है। यानी इस समय ममता बनर्जी के लिए चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली स्थिति बन चुकी है। इधर एसआईआर पर भी ऐसे-ऐसे खुलासे हो रहे हैं, जिनसे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अर्मत्य सेन के बाद जादवपुर विवि के कुलपति को चुनाव आयोग ने पेश होने का नोटिस दिया है। वहीं मंगलवार को बांकुड़ा जिले के खतड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक वाहन जब्त किया, जिसमें एसआईआर के करीब 3,000 फॉर्म-7 भरे हुए थे। पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। घटना में दो भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि फार्म-7 का इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी का नाम शामिल किए जाने का विरोध करने या किसी मृत या स्थानांतरित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए किया जाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में फार्म-7 ले जाने का उद्देश्य वैध मतदाताओं के नाम हटाना था। वहीं भाजपा ने सफाई में कहा कि हमारे बीएलए (बूथ स्तरीय एजेंट) जो बीएलओ (बूथ स्तरीय अधिकारी) को फॉर्म-7 जमा नहीं करा पाए थे, वे उन्हें ईआरओ (चुनाव पंजीकरण अधिकारी) कार्यालय में जमा कराने जा रहे थे। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया। उनकी पिटाई की और फार्म छीन लिए। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि फॉर्म उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोई भी मतदाता फॉर्म-7 जमा कर सकता है। फार्म-7 जमा करने मात्र से नाम मतदाता सूची से बाहर नहीं हो जाता। फार्म में दी गई जानकारी के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही नाम मतदाता सूची से बाहर किया जाता है।

क्या ईरान में इस्लामी शासन एक सोची-समझी क्रूर रणनीति का नतीजा है?

> आर्थिक पुनर्गठन प्रतिबंधों और भ्रष्टाचार ने ईरान की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। इसे पटरी पर लाने में दशकों लगेंगे। नई सरकार से जनता को तुरंत राहत की उम्मीद होगी और अगर वे विफल हुए, तो फिर से अराजकता फैल सकती है।

ईरान एक बार फिर उबल रहा है। तेहरान की सड़कों से लेकर कुर्दिस्तान के पहाड़ों तक, 'तानाशाही मुर्दाबाद' के नारे गूंज रहे हैं लेकिन यह पहली बार नहीं है। पिछले 17 वर्षों में ईरान कई बार इस दोराहे पर खड़ा हुआ है। हर बार जब जनता सड़कों पर उतरती है तो दुनिया को लगता है कि शायद इस बार इस्लामी गणराज्य की नींव हिल जाएगी लेकिन जैसे ही धूल छंटती है, अयातुल्ला का शासन और भी क्रूरता के साथ अपनी जगह पर कायम नजर आता है। आज वही पुराने सवाल फिर से फिजाओं में तैर रहे हैं कि आखिर ईरानी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्या करना होगा? हम कैसे जानेंगे कि हम उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि इतनी कोशिशों के बावजूद हर बार नाकामी ही क्यों हाथ लगती है? ईरान के इस्लामी शासन का टिके रहना कोई चमत्कार नहीं है बल्कि यह एक बेहद सोची-समझी और क्रूर रणनीति का नतीजा बताया जा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक-दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में, ईरान के पास अपने ही नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सबसे गहरा, सबसे व्यापक और सबसे प्रभावी सुरक्षा तंत्र है। ईरानी सत्ता की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (आईआरजीसी) और उसका अर्धसैनिक बल 'बासिज' है। बासिज कोई साधारण पुलिस बल नहीं है। यह समाज के भीतर बुना हुआ एक ऐसा नेटवर्क है, जिसमें आपके पड़ोसी, दुकानदार या साथ पढ़ने वाला छात्र भी मुखबिर हो सकता है। बासिज को शासन के दमनकारी मूल्यों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। जब विरोध होता है तो ये सादे कपड़ों में भीड़ में घुस जाते हैं, नेताओं की पहचान करते हैं और हिंसक कार्रवाई करते हैं। जानकारों के अनुसार चूंकि इनकी निष्ठा देश के प्रति नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर के प्रति होती है, इसलिए ये अपनी ही जनता पर गोली चलाने में हिचकिचाते नहीं हैं। ईरानी सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की नीति अपनाई है। मानवाधिकार समूहों और जेल से रिहा हुए

कैदियों की गवाही बताती है कि सरकार अब सिर्फ मारने में विश्वास नहीं करती, वह 'तोड़ने' में विश्वास करती है। अक्सर, सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करते हैं और उन्हें जेल में अमानवीय यातनाएं देते हैं लेकिन उन्हें हमेशा के लिए जेल में रखने के बजाय, कई बार उन्हें तब रिहा कर दिया जाता है। जब वे बुरी तरह पिट चुके होते हैं, उनका शरीर और मन टूट चुका होता है। इसके पीछे एक भयानक तर्क है कि जब एक मोहल्ले का लड़का जेल से वापस आता है और उसकी हालत देखकर उसके दोस्त और परिवार वाले सहम जाते हैं तो यह दूसरों के लिए डरावना सबक बन जाता है। इसे देखकर लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। ईरान में इंटरनेट शटडाउन तो आम बात है लेकिन वहां का सर्विलांस उससे कहीं आगे है। ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी करने वाले हजारों 'साइबर जासूस' तैनात हैं। वे सोशल मीडिया पर असंतोष की छोटी सी चिंगारी को भी आग बनने से पहले बुझाने का काम करते हैं। जानकारों के अनुसार ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए जरूरी होगा कि सुरक्षा बलों का पाला बदले लेकिन यह किसी भी क्रांति की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जब तक बंदूक थामने वाले हाथ सरकार के साथ हैं, सरकार सुरक्षित है। ईरानी सरकार के गंभीर रूप से गिरने के खतरे के लिए, यह अनिवार्य है कि सुरक्षा बलों की एक बड़ी संख्या विशेषकर नियमित सेना और पुलिस न कि आईआरजीसी पाला बदलकर प्रदर्शनकारियों में शामिल हो जाए या कम से कम, वे निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अयातुल्ला शासन आईआरजीसी और बासिज को इतना आर्थिक लाभ दिया जाता है कि वे अंत तक वफादार बने रहते हैं। अब तक के आंदोलनों की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं था। सरकार को गिराने के लिए एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो न केवल भीड़ को दिशा दे सके बल्कि सुरक्षा बलों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ भी बातचीत कर सके। बिना किसी स्पष्ट विकल्प के बहुत से लोग मौजूदा खराब व्यवस्था को अराजकता से बेहतर मानते हैं। ईरान की क्रांति (1979) तब सफल हुई थी जब तेल कर्मचारियों और बाजारियों यानी व्यापारी वर्ग ने हड़ताल कर दी थी। सरकार को घुटनों पर लाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ठप करना होगा। जब तक तेल बिक रहा है और पैसा रिवोल्यूशनरी गार्ड्स तक पहुंच रहा है, वे दमन जारी रखेंगे। ईरान में गत 17 सालों में कई कोशिशें हुई लेकिन सब फेल हो गई। 2009 ग्रीन मूवमेंट हुआ कारण था विवादित राष्ट्रपति चुनाव। लोगों ने पूछा- "मेरा वोट कहां है?" लाखों लोग सड़कों पर उतरे। यह 1979 के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन था लेकिन सरकार ने बेरहमी से कुचल दिया। सैकड़ों मारे गए, विपक्षी नेताओं (मीर हुसैन मौसवी, मेहदी करौबी) को नजरबंद कर दिया गया। यह आंदोलन मुख्य रूप से राजनीतिक था और मध्यम वर्ग तक सीमित था। इसी प्रकार वर्ष 2017-2018 में आर्थिक विद्रोह हुआ। वजह थी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार । यह आंदोलन तेहरान से नहीं बल्कि छोटे शहरों और गरीब तबकों से शुरू हुआ था। नारे थे- सुधारवादी, कट्टरपंथी खेल खत्म हुआं लेकिन सुरक्षा बलों ने हजारों को गिरफ्तार किया। चूंकि इसका कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, इसलिए इसे दबाना आसान था। वर्ष 2019 में पेट्रोल की कीमतों में अचानक 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने पर विद्रोह हुआ. बताया जा रहा है ईरान में यह सबसे हिंसक प्रदर्शन था। लोगों ने पेट्रोल पंप और बैंक जला दिए। इसे दबाने के लिए सरकार ने इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया और सेना उतार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक महज तीन दिनों में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। यह शासन की क्रूरता का चरम था। वर्ष 2022-23 में पुलिस हिरासत में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत होने पर महसा अमीनी और 'जिन, जियान, आजादी' के नाम पर आन्दोलन हुआ। यह आंदोलन 'हिजाब' के खिलाफ शुरू हुआ था लेकिन जल्द ही व्यवस्था परिवर्तन की मांग में बदल गया। इसमें महिलाओं और युवाओं ने नेतृत्व किया। ईरान में महीनों तक अशांति रही, 500 से ज्यादा मौतें हुईं। सरकार हिल गई थी।

रामस्वरूप रावतसरे

यह समस्या ...

अमरपाल सिंह वर्मा

न्याय व्यवस्था में जमानत और गरीबी का सवाल

राजस्थान हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले ने उस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं जिसमें जमानत और पैरोल की शर्तें कई बार गरीब कैदियों के लिए राहत नहीं बल्कि एक और सजा बन जाती हैं। कोर्ट ने हाल में उम्रकैद की सजा भुगत रहे एक कैदी खरताराम की चिट्ठी को ही याचिका मानकर सुनाए गए फैसले में कहा है कि गरीबी कोई अपराध नहीं है और न ही यह किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करने का आधार बन सकती है। पाली जिले का निवासी खरताराम हत्या के एक मामले में 2014 से सजा काट रहा है। जिला पैरोल कमेटी ने 29 सितंबर 2025 को उसे चौथी बार 40 दिन की नियमित पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया लेकिन इसके साथ 25-25 हजार रुपए के दो जमानती पेश करने की शर्त जोड़ दी गई। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होने के कारण खरताराम यह शर्त पूरी नहीं कर सका। उसके पास वकील करने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने जेल से ही पोस्टकार्ड भेजकर हाईकोर्ट से गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने न केवल उसकी याचिका सुनी बल्कि इस फैसले को ऐसे मामलों में एक नजीर के रूप में स्थापित कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि पैरोल या जमानत की शर्तें तय करते समय अधिकारियों को मशीनी रवैया छोडक़र मानवीय और संवैधानिक दृष्टि अपनानी होगी। यह फैसला केवल एक कैदी को राहत देने तक सीमित नहीं है बल्कि यह उस व्यापक समस्या की ओर इशारा करता

है जिसमें देश में हजारों गरीब कैदी फंसे हुए हैं। सवाल केवल पैरोल का नहीं है। सवाल उस व्यापक ढांचे का है जहां जमानत, पैरोल और अर्थदंड जैसे कानूनी प्रावधान गरीब व्यक्ति के लिए राहत नहीं बल्कि नई सजा बन जाते हैं। देश की जेलों में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे कैदी बंद हैं जिन्हें अदालतें जमानत या पैरोल दे चुकी हैं लेकिन पैसे के अभाव में वे सलाखों के पीछे ही पड़े हैं। कई ऐसे भी हैं जिनकी सजा की अवधि पूरी हो चुकी है मगर जुर्माना भरने में असमर्थ होने के कारण उन्हें रिहाई नहीं मिल पा रही। इस तरह कानून की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी कैद केवल इसलिए जारी रहती है क्योंकि वह व्यक्ति गरीब है। इसका सबसे सीधा असर जेलों पर पड़ता है। जेलें अपनी निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक भरी हुई हैं। विचाराधीन बंदियों की संख्या बहुत बड़ी है। जेलों में भीड़ के कारण कम जगह तथा सीमित संसाधनों का परिणाम खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में निकलता है। जेलों में अपराधियों को रखने के पीछे सुधार का मूल उद्देश्य भटक चुका है। यह समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर स्वयं राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को कहना पड़ा कि देश की जेलों में हजारों ऐसे कैदी बंद हैं जिनके पास जमानत पर रिहाई का कोर्ट आदेश तो है लेकिन जमानत राशि के पैसे नहीं हैं। उन्होंने अदालतों और सरकार से इन कैदियों के लिए समाधान निकालने की अपील की थी। राष्ट्रपति की इस टिप्पणी के दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्यों से रिपोर्ट तलब कर ली। इसके बाद फरवरी 2023 में सर्वोच्च अदालत ने इस मुद्दे पर सात महत्वपूण्र दिशा निर्देश जारी किए। अदालत की मंशा साफ है कि जमानत आदेश की सार्थकता तभी है, जब वह वास्तव में किसी को जेल से बाहर ला सके। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश एक रिपोर्ट में सामने आया कि जनवरी 2023 तक 5,380 ऐसे कैदी थे, जिन्हें जमानत मिल चुकी थी लेकिन वे अब भी जेलों में बंद थे। सबके मामलों में कारण पैसे का अभाव का ही था। 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल अदालतों को निर्देश दिए कि वे जमानत की शर्तें तय करते समय कैदियों की आर्थिक स्थिति पर भी विचार करें। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जमानत की शर्तें कैदी की हैसियत से परे हैं तो ऐसी जमानत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला भी इसी सोच की अगली कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की इसी संवैधानिक सोच का अनुसरण करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने अब यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसमें हाईकोर्ट ने माना है कि पैरोल एक सुधारात्मक अधिकार है, यह अमीरों का विशेषाधिकार नहीं है। कोर्ट ने अधिकारियों की उस प्रवृत्ति पर कड़ी नाराजगी जताई है जिसमें हर मामले में एक जैसी जमानत शर्तें थोप दी जाती हैं। यह भी नहीं देखा जाता है कि कैदी उन्हें पूरा करने की स्थिति में है या नहीं। हाई कोर्ट द्वारा जारी की गई छह सूत्रीय गाइडलाइन से इस बात का संकेत मिलता है कि अदालतें अब केवल आदेश देने तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बल देना चाहती हैं। अदालतें बार-बार निर्देश दे रही हैं लेकिन बड़ा सवाल है कि नीतियों और आदेशों का धरातलीय क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट पहले ही अनावश्यक गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत के बावजूद जेल में बंद रखने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जता चुका है। कोर्ट ने गरीब कैदियों की मदद के लिए एक मानक प्रक्रिया और फंड की व्यवस्था की बात भी कही है लेकिन अधिकांश राज्यों में यह पहल धरातल पर पहुंचने का इंतजार है। हाल में हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि वह गरीब कैदियों को जमानत या जुर्माना भरने में आर्थिक सहायता देगी। जमानत के लिए एक लाख रुपये तक और जुर्माने के लिए 25 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। यह एक सकारात्मक कदम है जिसे अपवाद नहीं बल्कि नियम बनाया जाना चाहिए।

पूजा हेगड़े और ...

सुभाष शिरढोनकर

पूजा हेगड़े के लिए उम्मीदों से भरा रहेगा साल 2026

एक्ट्रेस पूजा हेगड़े बॉलीवुड से ज्यादा साउथ फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हैं। साउथ के कंपेरिजन में हिंदी सिने जगत में उनका करियर कुछ खास नहीं रहा। पूजा हेगड़े ने साल 2016 में फिल्म 'मोहनजोदड़ो' से हिंदी सिने जगत में यह सोचकर डेब्यू किया था कि वह साउथ की तरह हिंदी सिने जगत में भी धूम मचा देंगी लेकिन उनकी यह डेब्यू हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इस तरह साउथ की तरह वे यहां अपना दबदबा कायम करने से चूक गईं। पूजा पिछले साल शाहिद कपूर के ऑपोजिट फिल्म 'देवा' (2025) में नजर आई थीं लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। रजनीकांत स्टारर पैन इंडिया फिल्म 'कुली' (2025) में उन्होंने एक डांस नंबर किया लेकिन इसमें भी उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिल सकी। साल 2025 बेशक पूजा की ख्वाहिशों को पूरा न कर सका हो लेकिन इस नये साल 2026 में पूजा ने एक बार फिर अपने मन में नई ख्वाहिशें पाल ली हैं। उन्हें लगता है कि उनके करियर के लिए जो काम बीता साल नहीं कर सका, वह काम यह नया साल 2026 अवश्य कर देगा। थलापति विजय के साथ वाली पूजा हेगड़े की फिल्म 'जन नायकन' 9 जनवरी को रिलीज हुई। यह फिल्म पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि थलापति विजय एलान कर चुके हैं कि यह उनके करियर की आखिरी फिल्म होगी और इसके बाद वह अपना पूरा फोकस पॉलिटिक्स पर करेंगे। थलपति विजय की आखिरी फिल्म होने की वजह से इसके प्रति काफी बज देखने को मिल रहा है। इस फिल्म को पैन इंडिया में रिलीज किया गया है और मेकर्स ने इसका हिंदी नाम 'जन नेता' रखा है। फिल्म में पूजा हेगड़े थलापति विजय के अपोजिट अहम रोल निभाया है। पूजा हेगड़े के अलावा फिल्म में बॉबी देओल एक बार फिर

विलेन के किरदार में हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के प्रदर्शन के नतीजों के लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा। 'जन नायकन' के बाद साल 2026 में पूजा हेगड़े की तीन और फिल्मों के रिलीज होने की उम्मीद की जा रही है। इनमें से एक डेविड धवन के निर्देशन पर बनने वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में वह वरुण धवन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। पूजा और वरूण धवन के अलावा फिल्म में मृणाल ठाकुर भी नजर आने वाली हैं। फिल्म में मनीष पॉल, मौनी रॉय, जिमी शेरगिल, चंकी पांडे, राकेश बेदी समेत कई स्टार्स नजर आएंगे। फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है', 5 जून को थिएटर्स में रिलीज होगी। इस मच अवेटेड फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है लेकिन फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच अभी से काफी उत्साह देखा जा रहा है साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर और सक्सेसफुल हॉरर–कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'कंचना' के मच अवेटेड सीक्वल 'कंचना 4' में पूजा हेगड़े, राघव लॉरेंस और नोरा फतेही के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। हालांकि अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन उम्मीद की जा रही है।

जरा हटके

ईरान ने पिछले चार ...

ललित गर्ग

ईरान की उथल-पुथल एवं अमेरिका से टकराव गंभीर चुनौती

ईरान में बार-बार उभरती उथल-पुथल केवल किसी एक घटना, किसी एक फैसले या किसी एक पीढ़ी का आक्रोश नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक, वैचारिक और भू-राजनीतिक संरचना की परिणति है, जिसने 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से इस देश को आकार दिया है। आज जब सड़कों पर विरोध के दृश्य, सोशल मीडिया पर आक्रोश और पश्चिमी विश्लेषकों की ओर से सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हैं, तब यह समझना जरूरी हो जाता है कि ईरान का संकट साधारण आंतरिक असंतोष नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन से गहराई से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ईरान की आंतरिक उथल-पुथल एवं अस्थिरता के साथ-साथ उसका अमेरिका के साथ टकराव युद्ध की स्थितियांे एवं वैश्विक असंतुलन का बड़ा कारण बन रहा ह ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव केवल द्विपक्षीय तनाव नहीं है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। इस संघर्ष से पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा बढ़ता है, जिसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की अस्थिरता अंतरराष्ट्रीय व्यापार की धमनियों को बाधित कर सकती है, जिससे महंगाई और आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ेगा। इसके साथ ही यह टकराव क्षेत्रीय देशों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध में खींच सकता है, जिससे शरणार्थी संकट, आतंकवाद और साम्प्रदायिक तनाव गहराने की आशंका है। महाशक्तियों के परस्पर टकराव की स्थिति में विश्व राजनीति और अधिक धूरवीकृत होगी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग कमजोर पड़ेगा और शांति की जगह अविश्वास व

सैन्य प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा, जिसका खामियाजा अंततः पूरी मानवता को भुगतना पड़ सकता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान में केवल शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को सत्ता से हटाकर एक नई सरकार स्थापित नहीं की थी, बल्कि एक ऐसी वैचारिक-राजनीतिक संरचना रची थी, जिसमें धर्म, राजनीति और सुरक्षा-तंत्र एक-दूसरे में घुलमिल गए। 'विलायत-ए-फकीह' की अवधारणा के तहत सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्व को अंतिम राजनीतिक अधिकार सौंपा गया। इसी व्यवस्था के संरक्षण और विस्तार के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी को खड़ा किया गया, जो समय के साथ केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक ताकत का भी केंद्र बन गया। यही कारण है कि ईरान की व्यवस्था को केवल सरकार या शासन कहकर नहीं समझा जा सकता; यह एक संपूर्ण तंत्र है, जिसे हटाने के लिए केवल विरोध-प्रदर्शन पर्याप्त नहीं होते। ईरान ने पिछले चार दशकों में कई बड़े जनांदोलन देखे हैं। 2009 का ग्रीन मूवमेंट, 2017-18 की आर्थिक असंतोष की लहर, 2019 में ईंधन मूल्य वृद्धि के खिलाफ उग्र प्रदर्शन और 2022 में सामाजिक स्वतंत्रताओं को लेकर उठी आवाजेंकृहर बार यह माना गया कि शायद अब व्यवस्था डगमगाएगी। लेकिन हर बार वही सत्ता, वही ढांचा और वही शक्ति-संतुलन कायम रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान में सुरक्षा-तंत्र राज्य से अलग नहीं, बल्कि राज्य का ही विस्तार है। अरब स्प्रिंग के दौरान मिस्र या तुर्किए में सेनाओं ने अंततः राष्ट्र-राज्य को बचाने का रास्ता चुना, लेकिन ईरान में आईआरजीसी खुद को क्रांति और इस्लामिक रिपब्लिक का संरक्षक मानती है, न कि केवल सीमाओं की रक्षा करने वाली संस्था। फिर भी यह कहना गलत होगा कि ईरान की व्यवस्था पर कोई दबाव नहीं है। वास्तव में, आज का दबाव पहले से कहीं अधिक जटिल और गहरा है। इसका सबसे बड़ा कारण है पीढ़ीगत बदलाव। ईरान की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है, जिसने 1979 की क्रांति न देखी है और न ही उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा है। उनके लिए क्रांति कोई जीवित स्मृति नहीं, बल्कि इतिहास की किताबों का अध्याय है। उनकी आकांक्षाएं इंटरनेट, वैश्विक संस्कृति, शिक्षा, रोजगार और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से प्रेरित हैं। जब ये आकांक्षाएं एक सख्त सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था से टकराती हैं, तो असंतोष स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। इस असंतोष को और तीखा बनाया है दशकों से चले आ रहे अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों ने। इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। तेल निर्यात सीमित हुआ, विदेशी निवेश रुका, मुद्रा कमजोर पड़ी और महंगाई ने आम नागरिक की कमर तोड़ दी। विकास और आधुनिकीकरण की गति धीमी पड़ी, जिससे खासकर शहरी मध्यम वर्ग और युवा वर्ग में भविष्य को लेकर निराशा बढ़ी। आज ईरान के कई नागरिक यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका और इजराइल के साथ अंतहीन दुश्मनी का बोझ उन्हीं के कंधों पर डाला जाना जरूरी है। धीरे-धीरे यह वैचारिक टकराव राष्ट्रवादी गौरव से अधिक सामाजिक बोझ के रूप में देखा जाने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव इस पूरे परिदृश्य को और खतरनाक बना देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के आदेश और सैन्य हस्तक्षेप के संकेतों ने पश्चिम एशिया को एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ईरान आज 1979 के बाद से शायद सबसे गंभीर बाहरी दबाव का सामना कर रहा है। यह टकराव केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा भू-राजनीतिक खेल बन चुका है, जिसमें महाशक्तियां अपने-अपने हित साधना चाहती हैं। अकसर यह धारणा बनाई जाती है कि बाहरी हस्तक्षेप से ईरान में सत्ता परिवर्तन संभव है। लेकिन इतिहास बताता है कि ईरान में विदेशी दखलअंदाजी ने हमेशा उल्टा असर डाला है। 1953 में मोसादेग सरकार के तख्तापलट से लेकर आज तक, 'विदेशी साजिश' का कथानक ईरानी राष्ट्रवाद को मजबूत करता रहा है। बाहरी समर्थन से होने वाले आंदोलनों को जनता का व्यापक और स्थायी समर्थन नहीं मिल पाता।

15 और 17 साल की खिलाड़ी फंदे पर टंगी मिली

केरल के एसएआई हॉस्टल की घटना, सुसाइड नोट नहीं मिला, मामले की जांच शुरू

कोल्लम, एजेंसी

केरल के कोल्लम जिले स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के हॉस्टल में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां दो नाबालिग महिला स्पोर्ट्स ट्रेनी के शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटके मिले। घटना की जानकारी मिलते ही खेल विभाग, पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। मृतक छात्राओं की पहचान कोझिकोड जिले की सैंड्रा (17) और तिरुवनंतपुरम जिले की वैष्णवी (15) के रूप में हुई है। दोनों छात्राएं SAI के कोल्लम सेंटर में अलग-अलग खेलों की ट्रेनिंग ले रही थीं और हॉस्टल में रहकर अभ्यास कर रही थीं। पुलिस के अनुसार, सैंड्रा एथलेटिक्स की ट्रेनी थी और कक्षा 12वीं में पढ़ाई कर रही थी, जबकि वैष्णवी एक उभरती हुई कबड्डी खिलाड़ी थी और कक्षा 10वीं की छात्रा थी। दोनों छात्राएं खेल के क्षेत्र में भविष्य बनाने की तैयारी कर रही थीं। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना की जानकारी मिलते ही SAI प्रशासन और खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हॉस्टल पहुंचे। इस घटना से खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है। हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं, कोचों और स्टाफ से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोनों छात्राओं पर किसी तरह का मानसिक दबाव तो नहीं था।

> पुलिस ने बताया कि वैष्णवी सामान्य तौर पर अलग कमरे में रहती थी, लेकिन बुधवार रात वह सैंड्रा के कमरे में सोने आई थी। हॉस्टल की अन्य छात्राओं ने भोर के समय दोनों को कमरे में देखा भी था। कमरे की तलाशी के दौरान कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे मामले की गुत्थी और उलझ गई है।

मौत का कारण अभी पता नहीं- पुलिस

कोल्लम ईस्ट पुलिस अब जांच में जुटी है। अधिकारियों ने बताया कि हॉस्टल में रहने वाली अन्य खेल छात्राओं, उनके ट्रेनर्स और दोनों लड़कियों के परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि मौत का कारण अभी पता नहीं चला है। यह सुसाइड है या कोई दूसरी वजह, यह जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।

सुबह की ट्रेनिंग में नहीं पहुंचीं, तब खुला मामला

घटना का खुलासा गुरुवार सुबह करीब पांच बजे हुआ। जब हॉस्टल में रहने वाली अन्य स्पोर्ट्स ट्रेनी सुबह के नियमित ट्रेनिंग सेशन के लिए निकलीं, तो सैंड्रा और वैष्णवी वहां मौजूद नहीं थीं। कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद हॉस्टल प्रशासन को सूचना दी गई। अधिकारियों ने दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया, जहां दोनों छात्राएं पंखे से लटकी हुई पाई गईं। यह दृश्य देखकर हॉस्टल में अफरा-तफरी मच गई।

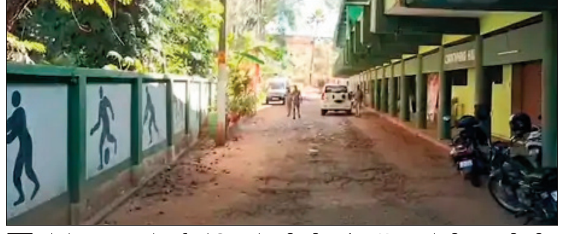

दोनों छात्राएं स्पोर्ट्स कोचिंग ले रहीं थी, और हॉस्टल में ही रह रही थीं।

11 साल पहले भी 4 विमेंस एथलीट ने सुसाइट की कोशिश की थी

केरल के साई सेंटर में इससे पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। करीब 11 साल पहले अलापुझा स्थित साई सेंटर में वॉटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहीं चार महिला एथलीट्स ने जहरीला फल खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। इन एथलीट्स ने अपने सीनियर्स और हॉस्टल वॉर्डन पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस घटना में अपर्णा नाम की एक एथलीट की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिस पर सभी एथलीट्स के हस्ताक्षर थे। जानकारी के मुताबिक, सभी पीड़ित लड़कियों ने साई विमेंस हॉस्टल में जहरीला फल (ओथलांगा) खाया था।

बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का बीसीबी डायरेक्टर को अल्टीमेटम

दोपहर तक इस्तीफा दो, वरना सभी फॉर्मेट का बायकॉट करेंगे

ढाका, एजेंसी

क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम को अल्टीमेटम दिया है कि अगर गुरुवार दोपहर 1 बजे तक वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो खिलाड़ी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट का बायकॉट करेंगे। अल्टीमेटम यह है कि उन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) मैच से पहले पद छोड़ना होगा, जो स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा। हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम के विवादित कमेंट पर अफसोस जताया है। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि ये कमेंट बोर्ड के ऑफिशियल रुख को नहीं दिखाते हैं। बोर्ड ने खिलाड़ियों का अपमान करने या बांग्लादेश क्रिकेट की साख को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार के लिए डिसिप्लेनरी एक्शन की चेतावनी दी है। जब इकबाल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के कारण दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों में मौजूदा तनाव को सुलझाने के लिए बातचीत का आह्वान किया था, 16 दिसंबर को IPL मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के कारण भारत में मुस्तफिजुर का विरोध होने लगा।

फास्ट न्यूज़

बीएमसी चुनाव में वोट करने बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगरपालिकाओं के लिए गुरुवार सुबह 7:30 बजे से मतदान जारी है। इस मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। एक्टर अक्षय कुमार पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे और वोट डाला।

उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग कर रहीं वायरल गर्ल मोनालिसा

देहरादून। प्रयागराज महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए सोशल मीडिया पर छा जाने वाली वायरल गर्ल मोनालिसा आज अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को जी रही हैं। कभी मेले में माला बेचने वाली मोनालिसा अब बॉलीवुड की दुनिया में कदम रख चुकी हैं और इन दिनों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अपनी डेब्यू फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' की शूटिंग में व्यस्त हैं। देहरादून के ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध खलंगा के जंगलों में फिल्म की शूटिंग चल रही है। कैमरों के बीच मोनालिसा का उत्साह साफ नजर आता है। वह कहती हैं कि कभी-कभी उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता कि एक साधारण सी जिंदगी से निकलकर वह यहां तक पहुंच गई हैं। उनके लिए यह सब किसी खूबसूरत सपने जैसा है, जिसे वह पूरी ईमानदारी से जी रही हैं।

इंफोसिस का मुनाफा तीसरी तिमाही में 2% घटा

मुंबई। आईटी कंपनी इंफोसिस ने 14 जनवरी को वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 2.2% गिरकर 6,654 करोड़ रहा। पिछले साल इसी तिमाही में 6,806 करोड़ का मुनाफा हुआ था। ऑपरेशन्स से होने वाला रेवेन्यू करीब 9% बढ़ा। यह 45,479 करोड़ पर पहुंच गया है, जो पिछले साल 41,764 करोड़ था।

हर्ष मेहता संग डेटिंग की खबरों पर मलाइका का रिएक्शन

एक्स अर्जुन कपूर को बताया लाइफ का अहम हिस्सा

मुंबई। मलाइका अरोड़ा को बीते साल डायमंड बिजनेसमैन हर्ष मेहता के साथ स्पॉट किया गया था, जिसके बाद उनकी लव लाइफ को लेकर अटकलें लगने लगी थी। अब एक्ट्रेस ने इन अफवाहों पर रिएक्शन दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक्स बॉयफ्रेंड एक्टर अर्जुन कपूर को लेकर भी बात की है। द नम्रता जकारिया के शो में अर्जुन के बारे में बात करते हुए मलाइका ने कहा, "वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ का अहम हिस्सा रहे हैं। मैं अपने अतीत या भविष्य के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। इस बारे में पहले ही बहुत कुछ लिखा और दिखाया जा चुका है। मेरी निजी जिंदगी मीडिया के लिए फीडिंग ग्राउंड बन गई है।₹ जब होस्ट ने अर्जुन से ब्रेकअप के बाद हर्ष के बारे में पूछा तो इस पर मलाइका कहती हैं- "लोगों को बातें करना पसंद है। अगर आपको किसी के साथ स्पॉट किया जाता, आप बाहर जाते हैं तो यह एक डिस्कशन का प्वाइंट बन जाता है। मैं बिना वजह इन बातों को हवा नहीं देना चाहती। मैं ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि इससे वास्तव में कोई फायदा नहीं होगा। यकीन मानिए, मैं जब भी बाहर निकली हूं, चाहे वह कोई पुराना दोस्त हो, गे फ्रेंड हो, शादीशुदा दोस्त हो, कोई पुराना दोस्त हो, मैनेजर हो या कोई भी हो...मेरा नाम तुरंत उस इंसान से जुड़ जाता हैं। हम इस पर हंसते और मजाक बनाते हैं।"

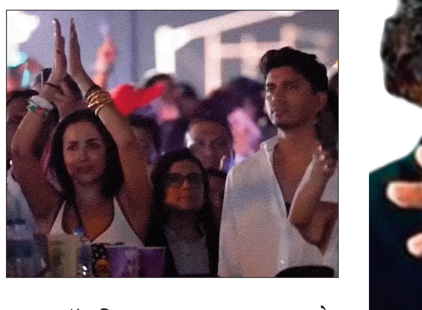

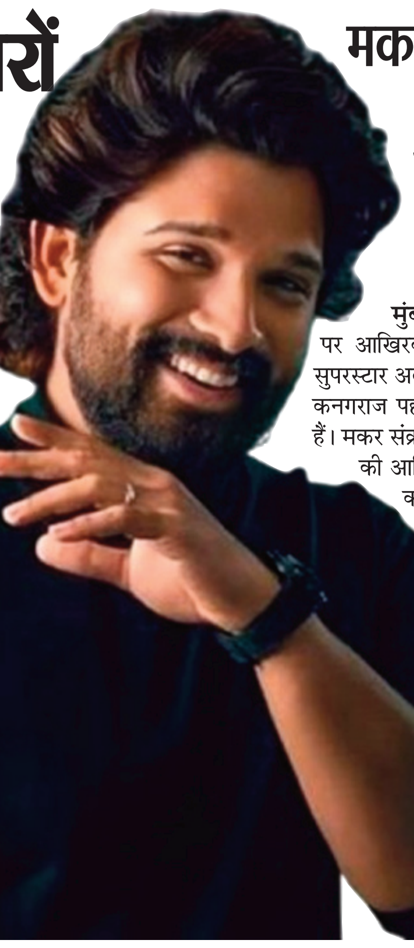

मकर संक्रांति के मौके पर मेकर्स ने एए23 की घोषणा की, एक्टर की 23वीं फिल्म होगी

अल्लू अर्जुन-लोकेश कनगराज की नई फिल्म अनाउंस

मुंबई। लंबे समय से चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है। पैन इंडिया सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और मशहूर निर्देशक लोकेश कनगराज पहली बार एक साथ काम करने जा रहे हैं। मकर संक्रांति के खास मौके पर इस मेगा प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। फिल्म को फिलहाल AA23 नाम दिया गया है, जो अल्लू अर्जुन के करियर की 23वीं फिल्म होगी। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की घोषणा प्रोडक्शन हाउस मैत्री मूवी मेकर्स ने एक खास वीडियो के जरिए की। अनाउंसमेंट वीडियो में बैकग्राउंड में '23' नाम का सॉन्ग सुनाई देता है, जिसे हाइजेनबर्ग ने लिखा है और हेक्टर सलामांका ने गाया है। वीडियो ने सोशल मीडिया पर आते ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया।

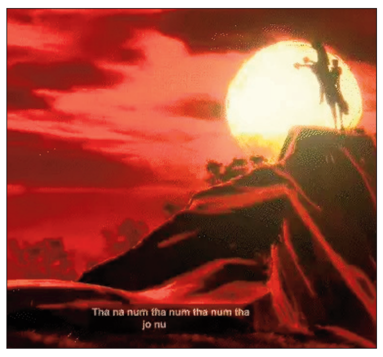

अल्लू अर्जुन बोले- नई यात्रा को लेकर उत्साहित

अल्लू अर्जुन ने भी AA23 के अनाउंसमेंट वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि वह मावरिक और लोकेश गरु के साथ इस नई सिनेमाई यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

> फिल्म की घोषणा करते हुए मैत्री मूवी मेकर्स ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा- "भारतीय सिनेमा का एक ऐसा कोलेबरेशन, जो अमर रहेगा। आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन और निर्देशक लोकेश कनगराज महानता के लिए प्रयास करते हुए। शूटिंग 2026 में शुरू होगी।"

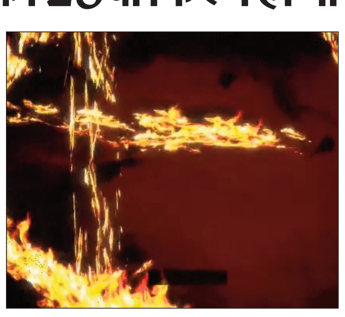

'स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस' टैगलाइन से झलकी फिल्म की थीम

फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो की टैगलाइन 'Strive for Greatness' रखी गई है, जो इशारों में फिल्म की सोच और थीम को दर्शाती है। मेकर्स के मुताबिक यह फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी और इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह पैन इंडिया लेवल का होगा। इस फिल्म का म्यूजिक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंदर देंगे, जिनका नाम जुड़ते ही प्रोजेक्ट को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई हैं। फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होने की तैयारी है।

ईरान की ओर बढ़ रहा अमेरिकी वॉरशिप

एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल, वेनेजुएला में हमले से पहले ऐसे ही घेराबंदी की थी

वॉशिंगटन, एजेंसी

ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच अमेरिका ईरान के आस-पास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी में है। अमेरिकी नौसेना का USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है। USS अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर-पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट न्यूज नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फैसला ईरानी एयरस्पेस के बंद होने के ठीक एक घंटे बाद लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, स्ट्राइक ग्रुप को चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी में तैनात किया था, लेकिन अब इसकी मूवमेंट देखी गई है। इसे मिडिल ईस्ट पहुंचने में करीब एक हफ्ता लग सकता है। हालांकि, अभी तक अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका ने वेनेजुएला में भी हमले से पहले इसी तरह तैनाती बढ़ाई थी। न्यूज नेशन की व्हाइट हाउस संवाददाता केली मेयर ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह ग्रुप अब साउथ चाइना सी से सेंट्रल कमांड (CENTCOM) क्षेत्र की ओर जा रहा है। जो मिडिल ईस्ट, उत्तर-पूर्वी अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के 21 देशों को कवर करता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में कोई अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद नहीं है। इससे पहले USS अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी में रूटीन ऑपरेशन कर रहा था। इसमें एक सुपरकैरियर, 3-6 डिस्ट्रॉयर्स, 1-2 पनडुब्बियां, 7000-8000 सैनिक और 65-70 विमान (F-35, F/A-18 आदि) शामिल हैं। इस ग्रुप में 1 क्रूजर भी शामिल किया जाता है, जो ऑपरेशंस के दौरान कमांड और कंट्रोल का काम करता है।

अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से कर्मचारियों को निकालना शुरू किया

अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने कुछ सैन्य अड्डों से कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स के अनुसार, कतर में स्थित अल उदैद एयर बेस (जो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है और करीब 10,000 सैनिक तैनात है) से कुछ कर्मचारियों को बुधवार शाम तक निकालने को कहा गया है।

कैरियर स्ट्राइक ग्रुप-3 का हिस्सा है यूएसएस अब्राहम लिंकन

USS अब्राहम लिंकन अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप-3 (CSG-3) का हिस्सा है, जिसमें एक न्यूक्लियर-पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल होती हैं। अमेरिकी नेवी की आधिकारिक वेबसाइट एपरपैक नेवी के मुताबिक, इस ग्रुप में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के साथ आम तौर पर 3 से 4 गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, एंटी-सबमरीन और लैंड-अटैक ऑपरेशन कर सकते हैं।

चीन का ट्रेड सरप्लस पहली बार रिकॉर्ड $1.19 ट्रिलियन पार

नई दिल्ली। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन का ट्रेड सरप्लस 2025 में रिकॉर्ड 1.19 ट्रिलियन डॉलर (करीब 100 लाख करोड़) के पार पहुंच गया है। यह 2024 के मुकाबले 20% ज्यादा है। महंगाई को एडजस्ट करने के बाद भी यह दुनिया के किसी भी देश का दर्ज किया गया अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस है। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के डेटा के मुताबिक, अकेले दिसंबर महीने में ही चीन ने 114.14 बिलियन डॉलर (करीब 10.31 लाख करोड़ रुपए) का सरप्लस कमाया। यह चीन के इतिहास का तीसरा सबसे सफल महीना रहा। निर्यात और आयात के बीच के अंतर को ट्रेड सरप्लस कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन पर 30% टैरिफ लगाया था। इससे अमेरिका के साथ चीन का सीधा व्यापार तो कम हुआ, लेकिन चीनी कंपनियों ने इसका तोड़ निकाल लिया। चीनी फैक्ट्रियों ने दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य क्षेत्रों के जरिए अमेरिका में सामान रूट किया।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के चलते शेयर बाजार बंद

नितिन कामथ बोले- लोकल इलेक्शन के लिए मार्केट बंद करना गलत

नई दिल्ली, एजेंसी

महाराष्ट्र में आज 15 जनवरी को नगर निगम चुनावों के चलते शेयर बाजार में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इस दिन पूरी तरह ट्रेडिंग छुट्टी घोषित की है। हालांकि, इस फैसले पर देश के सबसे बड़े ब्रोकरेज फर्म जिरोधा के को-फाउंडर नितिन कामथ ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे खराब प्लानिंग बताया है। शुरुआत में एक्सचेंजों ने इसे केवल 'सेटलमेंट हॉलिडे' घोषित किया था, यानी सिर्फ पैसों और शेयरों का लेन-देन बंद रहना था। लेकिन पिछले हफ्ते एक्सचेंजों ने नया सर्कुलर जारी कर बताया कि राज्य में बैंकों की छुट्टी होने के कारण अब पूरी तरह ट्रेडिंग बंद रहेगी। नितिन कामथ ने कहा- किसी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पूरे मार्केट को बंद करना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय बाजार अब ग्लोबल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इस तरह की छुट्टियां अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के सामने भारत की इमेज पर असर डालती हैं। कामथ ने दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे के साथी और बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन रहे चार्ली मंगर को कोट करते हुए लिखा- ₹मुझे इंसेंटिव दिखाओ और मैं तुम्हें आउटकम दिखा दूंगा। उनका इशारा था कि सिस्टम में कोई भी इस पुरानी व्यवस्था को बदलना नहीं चाहता। बाजार के जानकारों का कहना है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। ऐसे में बार-बार लोकल छुट्टियों की वजह से मार्केट बंद होने से विदेशी फंड हाउसों को हेजिंग और ट्रेडिंग में दिक्कत आती है।

क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल नहीं बदला

कंपनियों ने सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटाई

नई दिल्ली, एजेंसी

करीब एक लाख करोड़ का क्विक कॉमर्स सेक्टर थोड़ा बदला है। केंद्र के कड़े रुख के चलते ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट और फ्लिपकार्ट मिनट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ब्रांडिंग से '10-मिनट डिलीवरी' का दावा हटा दिया है। हालांकि इनके बिजनेस के तरीके नहीं बदले हैं। अब कंपनियां एप पर टाइमर के बजाय दूरी (जैसेः स्टोर 500 मीटर दूर है) दिखाने पर जोर दे रही हैं। बीएसई को दी गई जानकारी में ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी इटर्नल ने कहा है कि ब्रांडिंग बदलने से मुनाफा प्रभावित नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि टैगलाइन से '10 मिनट' हटाना बिजनेस मॉडल बदलने वाला फैसला नहीं है। कंपनियां 'फास्ट डिलीवरी' की ताकत नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि यही उनकी यूएसपी है। श्रम मंत्रालय के साथ हुई बैठक और राइडर सुरक्षा की चिंताओं के बाद, ब्लिंकिट ने अपनी ब्रांडिंग से '10-मिनट' के दावे को हटा दिया है। अब एप पर केवल 'मिनटों में डिलीवरी' जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। कंपनियों की सफाईः यह दोहराया गया है कि डिलीवरी पार्टनर्स को किसी निश्चित समय सीमा में सामान पहुंचाने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा। उनकी सुरक्षा व नियमों का पालन प्राथमिकता है। डार्क स्टोरी की दूरी दिखा रहींः कंपनी ने अब एप पर उपभोक्ता के स्थान से सबसे नजदीकी 'डार्क स्टोर' (यहां ये सामान पैक करके पहुंचाया जाता है) की दूरी दिखाना शुरू किया है, ताकि दिखाया जा सके कि कम दूरी के कारण ही डिलीवरी

चांदी तीन दिन में ₹34 हजार बढ़ी

नई दिल्ली। सोने-चांदी के दाम आज (14 जनवरी) को लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, एक किलो चांदी की कीमत 14,480 रुपए बढ़कर 2,77,512 रुपए हो गई है। कल इसने 2,63,032 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। तीन दिन में चांदी 34 हजार रुपए से ज्यादा महंगी हो चुकी है वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज 1,42,152 रुपए के ऑल टाइम हाई पर ओपन हुआ था। हालांकि इसके बाद सोने के दाम में थोड़ी कमी आई और ये 1,533 रुपए बढ़कर 1,42,015 रुपए पर बंद हुआ। कल इसकी कीमत 1,40,482 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। IBJA की सोने की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता। इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग होते हैं। इन रेट्स का इस्तेमाल RBI सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय करने के लिए करता है। कई बैंक गोल्ड लोन के रेट तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं।

0000: कुछ न कुछ हल निकालेंगे, ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री बोली- अमेरिका का गुलाम नहीं बनना

गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत : ट्रम्प

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की अपनी इच्छा दोहराई है। उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ हल निकल आएगा। ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को गोल्डन डोम नामक बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है। गोल्डन डोम अमेरिका का मिसाइल रक्षा प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है। गोल्डन डोम का मकसद चीन, रूस जैसे देशों से आने वाले खतरे से अमेरिका को बचाना है। उन्होंने कहा, "अमेरिका के साथ अपने सहयोग को मजबूत करना हमारे लिए ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अमेरिका के गुलाम होना चाहते हैं।" उन्होंने ट्रम्प के ग्रीनलैंड को खरीदने या कब्जा करने के विचार को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा, 'हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि यह डेनमार्क के हित में नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश आर्कटिक में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जिसमें ग्रीनलैंड में और ज्यादा अमेरिकी सैन्य अड्डे बनाने की संभावना भी शामिल है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने में डेनमार्क का समर्थन करने के लिए 13 लोगों की एक टीम भेजेगा। नॉर्वे के रक्षा मंत्री टोरे सैंडविक ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि नॉर्डिक देश आर्कटिक में NATO सदस्यों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीनलैंड में दो सैन्यकर्मियों को भेजेगा।

इजराइल की तरह अमेरिका भी मिसाइल अटैक से बचने के लिए डोम बनाने की तैयारी कर रहा है।

स्वीडन ने ग्रीनलैंड में सैन्यकर्मी भेजे, फ्रांस और जर्मनी भी टीम भेजेंगे

स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने बुधवार को कहा कि डेनमार्क के कहने पर स्वीडिश आर्म्ड फोर्स के कई अधिकारियों को एक सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए ग्रीनलैंड भेजा गया है। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी दोनों ने कहा है।

ट्रम्प बोले- नाटो को हमारी मदद करनी चाहिए

उन्होंने आगे कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड नहीं लिया, तो रूस या चीन इसे ले लेंगे और वे ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ट्रम्प का कहना है कि NATO को इस मामले में आगे आना चाहिए और अमेरिका को ग्रीनलैंड दिलाने में मदद करनी चाहिए।

> ट्रम्प का यह बयान व्हाइट हाउस में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों के बीच हुई हाई कमेटी बैठक के बाद आया है। इस बैठक में कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। बैठक के बाद ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोट्जफेल्ड ने कहा कि उन्हें अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद है। लेकिन ग्रीनलैंड पर अमेरिका का राज स्वीकार नहीं कर सकते।

ग्रीनलैंड पर चर्चा के लिए वर्किंग ग्रुप बनेगा

व्हाइट हाउस में बुधवार को हुई बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन और ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोट्जफेल्ट शामिल हुईं। इस बैठक में कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है। हालांकि, बैठक के बाद तीनों पक्षों ने ग्रीनलैंड से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति जताई, जिसकी बैठकें आने वाले हफ्तों में होंगी। रासमुसेन ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ असहमति बनी हुई है। हमारा रुख काफी अलग है।

लखनऊ कोर्ट ने 14 साल बाद आरोपी को बरी किया, जज बोले- सभी साक्ष्य संदेह वाले

झूठा एससी-एसटी केस दर्ज कराने वाली महिला पर एफआईआर होगी

न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त विल्सन सिंह उर्फ आशु के खिलाफ लगाए गए आरोप धारा 376, 506 भादंवि और एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुए। इसी आधार पर अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त पहले से जमानत पर था, ऐसे में उसका निजी मुचलका और जमानत नामे निरस्त कर जमानतदारों को दायित्व से मुक्त कर दिया गया।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में युवक पर झूठा SC-ST केस कराने वाली महिला पर FIR होगी। उसने जिस पर आरोप लगाया था उसे लखनऊ कोर्ट ने 14 साल बाद बरी कर दिया है। जज ने कहा है कि महिला के दिए गए सभी साक्ष्य संदेह से घिरे हैं। अब तक जितने बयान दिए गए, सब एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। ऐसे में महिला के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 344 के तहत FIR दर्ज की जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त बनाए गए युवक के मुचलके, जमानतनामे निरस्त कर दिए। यह फैसला लखनऊ के विशेष न्यायालय (SC/ST) ने सुनाया। यह निर्णय 12 जनवरी को विशेष

न्यायालय (SC/ST एक्ट) के न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। अभियुक्त विल्सन सिंह उर्फ आशु को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। यह मामला 9 अप्रैल 2011 को लखनऊ के विकास नगर थाने में दर्ज किया गया था। अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376

साक्ष्य आरोप सिद्ध करने में नाकाम रहे

विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। न्यायालय ने माना कि आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के लिए आरोपों का संदेह से परे सिद्ध होना अनिवार्य है, जबकि इस प्रकरण में यह कसौटी पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने फैसले में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की गवाह पीडब्ल्यू-2 सोनी कनौजिया द्वारा दिए गए बयान विरोधाभासी और मिथ्या पाए गए हैं।

(बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(12) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में लंबे समय तक चली।

बयान, मेडिकल रिपोर्ट और दस्तावेजों में विरोधाभास

सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गंधर्व गौड़ ने अदालत के समक्ष यह तर्क प्रभावी रूप से रखा कि पीड़िता के बयान अलग-अलग चरणों में आपस में मेल नहीं खाते। जिरह के दौरान यह भी सामने आया कि मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन के कथनों का पूर्ण समर्थन नहीं करते। अदालत ने अपने आदेश में इन विरोधाभासों को गंभीर माना। इस आधार पर न्यायालय ने शिकायतकर्ता के विरुद्ध धारा 344 CrPC के तहत अलग से कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए और इस संबंध में सूचना पत्र जारी करने का आदेश दिया।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से बदला कानपुर का ऊर्जा नक्शा

20,756 सोलर रूफटॉप सिस्टम से 64 मेगावाट बिजली, सालाना 38 करोड़ तक की बचत

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। नगर विकास से मोरिया मंत्री श्री के शर्मा के नेतृत्व में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नीति नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है।इसी क्रम में कानपुर नगर में बिजली उत्पादन का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत शहर की छतों पर स्थापित सोलर रूफटॉप सिस्टम से करीब 64 मेगावाट क्षमता की सौर बिजली तैयार हो रही है। अब तक जिले में 20,756 सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए जा चुके हैं, जिससे उत्तर प्रदेश नेडा के आंकड़ों के अनुसार सोलर रूफटॉप स्थापना के मामले में कानपुर नगर प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। शहर की छतें अब छोटे-छोटे पावर हाउस के रूप में उभर रही हैं। इस उपलब्धि पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने जनपदवासियों को बधाई दी

है।ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार 64 मेगावाट सौर उत्पादन सालाना लगभग 9.6 करोड़ यूनिट स्वच्छ ऊर्जा के बराबर है। मौजूदा बाजार दरों के आधार पर इस बिजली का वार्षिक आर्थिक मूल्य करीब 34 से 38 करोड़ रुपये आंका जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इतनी मात्रा में बिजली पारंपरिक स्रोतों से खरीदी जाए, तो सरकार, संस्थानों और उपभोक्ताओं को हर वर्ष इतनी बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती। छतों पर सोलर संयत्र स्थापित करवाने वाले लोगों के बिजली के बिल भी कम आ रहे हैं।फरवरी 2024 से शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत जिले में सोलर रूफटॉप स्थापना की रफ्तार लगातार बनी हुई है। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 80 से 90 नए सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। व्यक्तिगत आवासों के साथ-साथ बहुमंजिला भवनों और हाउसिंग सोसाइटियों के कॉमन एरिया में भी सोलर सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे शहरी स्तर पर विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन का आधार मजबूत हो रहा है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों के मुताबिक 64 मेगावाट सौर उत्पादन से सालाना करीब 80 हजार टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आती है, जिसे पर्यावरणीय दृष्टि से लगभग 35 लाख पेड़ों के बराबर लाभ माना जा रहा है। इसके अलावा इतनी क्षमता से प्रतिदिन औसतन 30 से 35 हजार शहरी घरों की बिजली जरूरत पूरी की जा सकती है।

फास्ट न्यूज

एसजीपीजीआई में नए मरीज नहीं देखे जाएंगे

लखनऊ। SGPGI में आज (15 जनवरी को) OPD में नए पंजीकरण नहीं होंगे। प्रदेश सरकार की ओर से मकर संक्रांति के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके बाद SGPGI प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। संस्थान प्रशासन के अनुसार OPD में नए पंजीकरण नहीं होंगे, लेकिन जिन पुराने रोगियों को OPD परामर्श के लिए पहले से ही तारीख दी गई है।

मुरादाबाद में फिर नजर आया तेंदुआ

मुरादाबाद। मुरादाबाद में एक बार फिर तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अभी 20 दिन पहले ही तेंदुए ने गेहूं के खेत की सिंचाई कर रहे एक किसान पर हमला कर दिया था। अब फिर से तेंदुआ नजर आने से ग्रामीणों में खौफ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। ताजा मामला भोजपुर थाना क्षेत्र में धारक नगला को जाने वाले रोड पर मिलक और खैय्या खादर गांव के बीच का बताया जा रहा है। तेंदुए की एक वीडियो भी सामने आई है। कार सवार युवकों ने वीडियो रिकॉर्ड किया। इनका दावा है कि वीडियो बुधवार रात करीब 12 बजे का है। भोजपुर थाना क्षेत्र के धारक नगला रोड जाने वाली रोड निकट मिलक और खैय्या खद्दर के गांवों के बीच में बुधवार की रात्रि को लगभग 12:00 बजे तेंदुआ दिखाई दिया।

बीमारी का बहाना बनाकर ₹45 हजार की ठगी

आलमबाग। कृष्णानगर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया है। एक युवक से बीमारी का बहाना बनाकर 45 हजार रुपए ठग लिए गए। पीड़ित कृष्णानंद सिंह ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कृष्णानंद सिंह के अनुसार, वह आरोपी को पहले से जानते थे, जो वर्तमान में दुबई में रहता है। 7 जनवरी 2026 को आरोपी ने मोबाइल फोन पर उनसे संपर्क किया।

वाटर पार्क घूमने गई सगी बहनों से छेड़छाड़

छोटी बहन के विरोध पर तेजाब डालने की धमकी दी

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। कानपुर में शोहदों की दुस्साहस का मामला सामने आया है। वाटर पार्क घूमने पहुंची सगी बहनों से 8-10 शोहदों ने छेड़छाड़ की। विरोध किया तो शोहदों ने सरेआम दुपट्टा खींच लिया। तेजाब डालने और वीडियो बनाकर वायरल की धमकी दी। युवतियों के शोर मचाने पर पार्क में घूम रहे लोग आगे आए तो आरोपी धमका कर कार में बैठकर भाग निकले। घर पहुंचने पर डरी-सहमी बहनों ने परिजनों को आपबीती बताई। तब जाकर उनकी मां ने आरोपियों के खिलाफ बुधवार रात नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तौधकपुर दीनदयालपुरम क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की मां ने बताया- मंगलवार को मेरी 19 और 14 साल की दो बेटियां अपने पांच छोटे भाई-बहनों के साथ आवास विकास हंसपुरम में वाटर पार्क

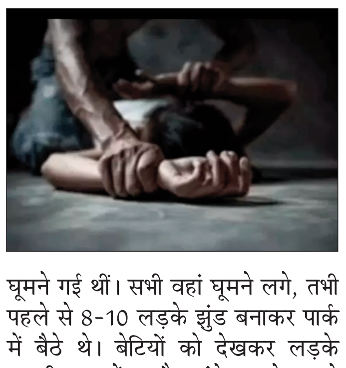

घूमने गई थीं। सभी वहां घूमने लगे, तभी पहले से 8-10 लड़के झुंड बनाकर पार्क में बैठे थे। बेटियों को देखकर लड़के अश्लील कमेंट और गंदे इशारे करने लगे। बेटियों ने उनकी हरकतों को नजर-अंदाज किया और घूमती रहीं। इसी बीच लड़के बेटियों के पीछे लग गए। इसका बेटियों ने विरोध किया तो लड़के गाली देने लगे। लड़कों की हरकत से बेटियां डर गईं और पार्क की सुरक्षा में तैनात गार्ड से शिकायत करने के लिए आगे बढ़ीं तो आरोपी भड़क गए।

शराब-सिगरेट के लिए दोस्त की हत्या, पेट्रोल डालकर लाश जलाई

लखनऊ में सिर पर गमला पटका, गिरते ही चाकू से गला रेत दिया

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में शराब-सिगरेट के लिए युवक की दो दोस्तों ने हत्या कर दी। पहले उसके सिर पर गमला मारा। फिर बेहोश होते ही चाकू से गला रेत दिया। पहचान छिपाने के लिए पेट्रोल छिड़ककर शव को आग लगा दी। पुलिस ने युवक की पहचान नगराम के टिकरा गांव निवासी सचिन तिवारी के रूप में की है। पुलिस के मुताबिक, सचिन ने दोस्त निहाल के घर पर शराब पार्टी दी थी। तभी शराब खत्म होने पर उनका विवाद हो गया। दोस्तों ने सचिन के शव को जलाकर भागीरथी एन्क्लेव के पास फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपी दोस्तों को बुधवार को अरेस्ट किया है। घटना 7 जनवरी की सुशांत गोल्फ सिटी इलाके की है। निहाल ने सचिन की हत्या के बाद ममेरे भाई करन वाल्मीकि को भी

सचिन तिवारी, मृतक

फोन करके बुलाया। इसके बाद तीनों ने मिलकर शव को पहले चादर में लपेटा। फिर प्लास्टिक में बांधकर स्कूटी पर लाद लिया। शव को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। पुलिस ने तीसरे आरोपी के नाम का अभी तक खुलासा नहीं किया है। तीनों आरोपियों ने भागीरथी एन्क्लेव के पास रास्ते में एक सुनसान खाली मैदान देखकर शव को दूसरी तरफ फेंक दिया। इसके बाद आरोपी पेट्रोल लेने नीलमथा गए, जहां बोतल में पेट्रोल देने से मना कर दिया गया। तब स्कूटी में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाकर आरोपी दोबारा शव के पास पहुंचे और अपने मफलर से स्कूटी में तेल निकालकर शव पर छिड़ककर उसको जला दिया। सुशांत गोल्फ सिटी इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया- घटना के समय निहाल की मां बगल के कमरे में मौजूद थी। हत्या के बाद उन्हें घटना की जानकारी हुई। जिस पर उन्होंने खुद ही शव ढकने के लिए चादर दी। इसके बाद निहाल ने करन को फोन करके घर बुलाया और स्कूटी से आने को कहा। निहाल की मां और करन ने मिलकर घर में हुई हत्या के सबूत मिटाने की कोशिश की। घटना के बाद से निहाल की मां मां और एक दोस्त फरार है, जिसका नाम विनय बताया जा रहा।

दलित छात्र की हत्या, लाश ट्रैक पर फेंकी

पिता बोले- गर्लफ्रेंड के घरवालों ने मर्डर किया

तमसा संकेत, एजेंसी

सहारनपुर। सहारनपुर में 14 साल के दलित लड़के की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने हत्या को सुसाइड दिखाने के लिए लाश को बोरे में भरकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। लोको पायलट ने ट्रैक पर बोरी देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरी खुलवाई, जिसमें लाश पड़ी थी। लाश मिलने की सूचना पर परिजन पहुंचे और मयंक के रूप में शव की पहचान की। पिता का आरोप है कि बेटे का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। लड़की ने ही उसे धोखे से मिलने बुलाया, इसके बाद उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, फिर शव को फेंक दिया। पिता ने चार लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। घटना बुधवार रात की है। देवबंद

मयंक, मृतक

कोतवाली क्षेत्र के गांव अलीपुर निवासी रूपचंद किसान हैं। उन्होंने बताया- मेरा बेटा मयंक देवबंद के एक इंटर कॉलेज में नौवीं में पढ़ता था। उसका अपनी ही जाति की एक युवती से प्रेम प्रसंग था। सोमवार देर रात 12:45 बजे बेटे को लड़की के घर से फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाया। घरवालों को लगा कि किसी परिचित का फोन है, इसलिए उन्होंने बेटे से ज्यादा पूछताछ नहीं की।

18 करोड़ का आईटीसी घोटाला

फर्जी फर्म बनाकर 99 करोड़ का लेन-देन दिखाया, कागजों पर कारोबार

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। आगरा में बोगस फर्म बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। फर्म संचालक ने रजिस्ट्रेशन के बाद दो फर्मों से खरीद दिखाई। 99 करोड़ रुपए से अधिक का लेन-देन दिखाया। जांच में पता चला कि किसी सामान की खरीद-फरोख्त नहीं की गई। सिर्फ पेपर तैयार उनका अदान-प्रदान कर बोगस ITC का लाभ लिया। आरोप है कि फर्जी फर्म बनाकर 18 करोड़ रुपए के ITC की चोरी की गई। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद फर्म का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। व्यापारी पर आगरा के थाना लोहामंडी थाना में FIR दर्ज कराई गई है। उपायुक्त राज्य कर खंड-12 अशोक कुमार सिंह ने थाना लोहामंडी में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में बताया गया है कि एसके ट्रेडर्स के मालिक सुरेश कुमार चाहर की फर्म का पता अमरपुरा, जगदीशपुरा दर्शाया गया था।

जांच में सामने आया कि फर्म का 27 सितंबर 2017 को विभिन्न वस्तुओं की खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया गया था। रजिस्ट्रेशन के दौरान सुरेश कुमार चाहर ने अपना स्थायी पता छतरपुर, मध्य प्रदेश बताया था। इसके साथ ही उसने अपनी फोटो, किरायानामा, रजिस्ट्री की प्रति और बैंक स्टेटमेंट भी पोर्टल पर अपलोड किए थे, जिसके आधार पर फर्म का रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया गया। इन फर्जी लेन-देन की गहन जांच के दौरान व्यापारी का बड़ा घोटाला उजागर हुआ। जांच एजेंसियों को पता चला कि व्यापारी ने वास्तविक खरीद किए बिना केवल कागजी लेन-देन दिखाकर बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ लिया। बताया जा रहा है कि इस तरह व्यापारी ने फर्जी फर्में बनाकर करीब 18 करोड़ रुपए के ITC की चोरी की। बाद में जांच के दौरान 11 दिसंबर 2018 को प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया। इसके बावजूद व्यापारी द्वारा दो फर्मों से खरीद दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा किया गया। जांच में पाया गया कि अजमेर की राधे इंटरनेशनल नामक फर्म से 9.48 करोड़ रुपये की ITC क्लेम की गई थी, जबकि यह फर्म फर्जी पाई गई। राधे इंटरनेशनल का रजिस्ट्रेशन पहले ही 20 नवंबर 2019 को निरस्त किया जा चुका था। ACP लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया- इस मामले में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की धारा में FIR दर्ज की गई है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

छापेमारी : काशी में पुलिस पहुंची तो पति भागा, पत्नी पकड़ाई, कमरे में न्यूड लड़के-लड़कियां मिले

पति-पत्नी 5 मंजिला घर में चला रहे थे सेक्स रैकेट

- 2 लड़के और एक लड़की और एक महिला को पुलिस ने पकड़ा है।
- पुलिस ने कमरे के दरवाजा तोड़कर चेकिंग की।
- कमरे में शराब की बोतलें और अन्य आपत्तिजनक सामान मिला है।

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी। वाराणसी में पति-पत्नी स्पा सेंटर की आड़ में अपने 5 मंजिला घर में सेक्स रैकेट चला रहे थे। बुधवार रात पुलिस ने छापेमारी की तो अफरा-तफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। स्पा संचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दो कमरों के दरवाजे तोड़कर स्पा सेंटर की मालकिन समेत 2 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया। पुलिस को कुछ युवक-युवतियां नग्न मिले। दो युवक और एक

समीर सिद्दीकी | तरन्नुम सिद्दीकी

युवती आपत्तिजनक हालत में पाए गए। कमरों से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। स्पा सेंटर कैंट इलाके के मकबूल आलम रोड पर है। यहां से पुलिस अफसरों की कॉलोनी की दूरी सिर्फ 500 मीटर है। दो महीने पहले मोहल्ले वालों ने शिकायत की थी, इसके बाद से पुलिस छापेमारी कर रही थी। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला तरन्नुम और पकड़े गए युवक-युवती से पूछताछ कर रही है। उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। आजाद नगर कॉलोनी में सैयद समीर (32) परिवार के साथ रहते हैं। उनके तीन बच्चे हैं—17 और 10 साल की दो बेटियां और 8 साल का एक बेटा। वे अपने 5 मंजिला मकान में स्पा सेंटर चलाते थे। फिर धीरे-धीरे उन्होंने इसे देह व्यापार

एसीपी कैंट नितिन तनेजा ने बताया- पुलिस टीम के छापा मारते ही समीर सिद्दीकी मौके से भाग गया, जबकि उसकी पत्नी तरन्नुम को गिरफ्तार कर लिया गया। एक कमरे में दो युवक और एक युवती आपत्तिजनक हालत में मिले। इसके बाद पुलिस ने अन्य कमरों की तलाशी ली। दो कमरों में ताले लगे थे।

का अड्डा बना दिया। मकान के एक हिस्से में किरायेदार भी रहते हैं। समीर की पत्नी तरन्नुम (30) भी इसमें शामिल हो गई। स्पा सेंटर

की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट में रोज बड़ी संख्या में लड़के-लड़कियां आने लगे। यह सेक्स रैकेट पिछले 2 साल से चल रहा था। समीर सिद्दीकी ने बाहर "एसके इंटर-प्राइजेज" का बोर्ड लगा रखा था, ताकि किसी को इस धंधे का पता न चल पाए। हैरानी की बात यह है कि लंबे समय तक किसी को इसकी भनक नहीं लगी। करीब 2 महीने पहले मोहल्ले के लोगों ने शक के आधार पर पुलिस से शिकायत की।

पृष्ठ 01 का शेष...

भारत से संघर्ष के ...

इसको लेकर दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों के बीच बातचीत हो चुकी है। इसी तरह रॉयटर्स की रिपोर्ट मे दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने 7 जनवरी को सऊदी अरब को JF-17 बेचने को लेकर बात की है। पाकिस्तान सऊदी अरब से मिले 2 अरब डॉलर के लोन के बदले यह सौदा कर रहा है। हालांकि, रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी सेना ने अभी तक लीबिया या सऊदी अरब के साथ इस समझौतों को लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। बांग्लादेश ने भी अभी तक पाकिस्तान के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए हैं।रॉयटर्स की 9 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 सालों में कई देशों ने पाकिस्तान का JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जताई है। नाइजीरिया, म्यांमार और अजरबैजान के मिलिट्री बेड़े में पहले से ही यह जेट शामिल है। अल-जजीरा के मुताबिक, इसके पहले पाकिस्तान ने दिसंबर 2025 में लीबिया के विद्रोही गुट, लीबियाई नेशनल आर्मी (LNA) को 4 अरब डॉलर में एक दर्जन से ज्यादा JF-17 फाइटर जेट बेचने का सौदा किया था। ये पाकिस्तान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की डील कही जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान सुडान के साथ भी 12,500 करोड़ रूपए की डिफेंस डील करने वाला है, जिसमें JF-17 फाइटर जेट भी शामिल हैं। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक, JF-17 थंडर एक मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, JF-17 फाइटर जेट के निर्माण में लगभग 58% हिस्सा पाकिस्तान और 42% हिस्सा चीन का है। वहीं इसमें लगा क्लिमोव RD-93 इंजन और नए ब्लॉक 3 में लगा RD-93 MA इंजन रूस में बना है। रूस ये इंजन चीन के जरिए पाकिस्तान को मुहैया कराता है।

जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर जून 2007 में तैयार किया था। इसका डिजाइन और टेक्नोलॉजी चीन की चेंगड़ू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (CAC) ने तैयार किया है और पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स (PAC) ने इसकी फाइनल एसेंबलिंग की है। खास बात ये है कि इसका इंजन रूस में बना है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय चीन और पाकिस्तान के पास आधुनिक फाइटर-जेट इंजन उपलब्ध नहीं था। JF-17 फाइटर जेट के निर्माण में लगभग 58% हिस्सा पाकिस्तान और 42% हिस्सा चीन का है। वहीं इसमें लगा क्लिमोव RD-93 इंजन और नए ब्लॉक 3 में लगा RD-93 MA इंजन रूस में बना है। रूस ये इंजन चीन के जरिए पाकिस्तान को मुहैया कराता है।

मंदिर में तोड़फोड़...

घटनाक्रम बढ़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। इसके बाद इलाके में स्थिति नियंत्रित की गई। देर रात तक पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) सहित अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। गश्त बढ़ा दी गई है और संवेदनशील स्थानों पर पिकेट्स लगाए गए हैं। पुलिस ने कामतीपुरा थाना में दो केस दर्ज किए हैं। पहला मामला मंदिर परिसर में घुसपैठ कर मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। दूसरा मामला विरोध प्रदर्शन के दौरान दरगाह को नुकसान पहुंचाने की घटना से संबंधित है। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इलाके का दौरा किया और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

बीएमसी चुनाव ...

यूबीटी जहां 163 सीटों पर लड़ी वहीं MNS को 52 सीट मिली। कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) से गठबंधन किया है। कांग्रेस 143 सीटों पर लड़ रही है वहीं वीबीए को 46 सीट दी गईं हैं। एनसीपी ने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया। अजित गुट वाली ये पार्टी 94 सीटों पर लड़ रही है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने कहा- वोटर की उंगली पर लगी स्याही को मिटाने की कोशिश करना और इस तरह वोटरों के बीच कन्फ्यूजन पैदा करना एक गलत काम है। अगर यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी उंगली से स्याही मिटा दी है और दोबारा वोट देने आया है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई उंगली पर लगी स्याही मिटाकर गलत काम करने की कोशिश करता है, तो भी संबंधित वोटर दोबारा वोट नहीं दे सकता। इस संबंध में जरूरी सुरक्षा उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। एक बार जब कोई वोटर वोट डाल देता है, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि नागपुर में नगर निगम चुनाव से पहले लोगों के एक ग्रुप के साथ झड़प में एक BJP उम्मीदवार घायल हो गया। यह घटना गुरुवार आधी रात के आसपास हुई। पार्टी के शहर प्रमुख दयाशंकर तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि नागपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 11 से BJP उम्मीदवार भूषण शिंगणे गोरेवाड़ा इलाके में गए थे, जब उन्हें पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने और पैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब शिंगणे मौके पर पहुंचे, तो 100 से ज्यादा लोगों के एक ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया और वे घायल हो गए। कांग्रेस 143 सीटों पर लड़ रही है वहीं वीबीए को 46 सीट दी गईं हैं। एनसीपी ने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया। अजित गुट वाली ये पार्टी 94 सीटों पर लड़ रही है।

बारा टोल प्लाज़ा पर अधिवक्ता से मारपीट

वकीलों का उग्र विरोध - तीन टोल कर्मी हिरासत में

तमसा संकेत, संवाददाता

बाराबंकी। हैदरगढ़ लखनऊ–सुल्तानपुर हाईवे स्थित बारा टोल प्लाज़ा पर एक हाईकोर्ट अधिवक्ता के साथ टोल कर्मियों द्वारा की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले भर के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। बुधवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता टोल प्लाज़ा पहुँचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फास्टैग/टोल भुगतान को लेकर हुए विवाद के दौरान टोल कर्मियों और अधिवक्ता के बीच कहासुनी बढ़ गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि अधिवक्ता को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया और जबरन माफी मंगवाई गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अधिवक्ता संगठनों ने इसे कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग

की। हैदरगढ़ कोतवाली पुलिस ने पीड़ित अधिवक्ता की तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, मामले में तीन टोल कर्मियों को हिरासत में लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676